विवरण-II

500 करोड़ रु० अथवा इससे अधिक की लागत वाली चुनिन्दा चल रही सिंचाई बहुउद्देश्यी परियोजनाओं तथा ऐसी परियोजनाएं जो राज्यों की संसाधन क्षमता से बाहर हैं अथवा जो निर्माण की उन्नत अवस्था में है तथा जिन्हें थोड़ी सी अतिरिक्त निधियां प्रदान करके पूरा किया जा सकता हो उनको शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से वर्ष 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत राज्यों को 50% मैचिंग आधार पर ऋण के रूप में निधियां प्रदान की जाती हैं। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार को केन्द्रीय ऋण सहायता राज्य से इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर इस वचनबद्धता पर दी जाती है कि सम्बद्ध राज्य अपने हिस्से का निवेश करेंगे। जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता एवं लाभान्वित परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:—

वर्ष	केन्द्रीय ऋण सहायता (करोड़ रु० में) बजट आवंटन	जारी राशि	लाभान्वित परियोजनाओं की संख्या (संचयी)
1996-97	500.00	500.00	52
1997-98	1300.00	952.19	80
1998-99	1500.00	679.43	93 (15.2.99 तक)

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत लाभान्वित परियोजनाओं के माध्यम से सृजित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता अब तक लगभग 219027 हैक्टे० है।

National Commission for Integrated Water Resource Development

453. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether a National Commission for Integrated Water Resource Development has been set up;

(b) if so, whether an integrated Water Plan for development of water resources for Drinking, Irrigation, Industrial, Flood Control and other uses has been prepared;

(c) whether modalities for transfer of surplus water to water-deficit basin by inter-linking of rivers has been suggested by the National Commission;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the details of the important ongoing projects with their present status?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): (a) to (e) Ministry of Water Resources has set up a National Commission for Integrated Water Resources Development Plan on 13.9.96. The terms of reference of the National Commission interalia include to suggest modalities for transfer of surplus water to water deficit basin by inter-linking of rivers for achieving the objective of peparing an integrated water plan for development of water resources for Drinking, Irrigation, Industrial, Flood Control and other uses. The Commission has not submitted its report.